

(b) the steps taken to increase the production of jute in the State;

(c) the schemes drawn up therefor; and

(d) the details of the funds allocated to West Bengal for the purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) The total production of jute in West Bengal during the last three years is as follows:—

Year	Production (‘000 bales of 180 kg. each)
1992-93	5347.2
1993-94	5569.0
1994-95	5934.2

(b) to (d) In order to increase the productivity and improve the quality of jute fibre, Government of India is implementing a Centrally Sponsored Scheme of ‘Special Jute Development Programme’ in West Bengal since 1987-88. The entire cost of this scheme is being borne by the Govt. of India. Under the scheme, Government of India is providing financial assistance in the form of incentives to the State Govt. of West Bengal on (i) distribution of seed (ii) distribution of implements like multi-row seed drill and wheel hoe (iii) conducting demonstration on production technology (iv) distribution of essential nutrient minikits, (v) foliar spraying of urea (vi) post harvest operation

like excavation of kutchha retting tank and distribution of fungal culture packets (vii) conducting training at State/district/farm level and (viii) contingencies.

A sum of Rs. 211.42 lakh has been allocated to the State Government of West Bengal for the implementation of Special Jute Development Programme in their State during 1995-96.

उत्तर प्रदेश में पशुपालन का विकास करने के संबंध में प्रस्ताव

6555. प्रो. राम बख्श सिंह वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पशुपालन का विकास करने के लिये कोई प्रस्ताव पेश किया है ?

(ख) यदि हाँ, तो इसका व्यौरा क्या है ? और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में पशुपालन के संवर्धन हेतु कौन-कौन से कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) राज्य में पशुपालन विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चालू वर्ष 1995-96 में अभी तक कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है ।

(ग) उत्तर प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये, भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित

योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता प्रदान की है। प्रत्येक योजना

के अन्तर्गत प्रदान की गई सहायता का औसत नीचे दर्शाया गया है—

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	योजना	1992-93	1993-94	1994-95
1.	हिमालय प्रौद्योगिकी तथा चतुर्दिशीय परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार	44.23	14.00	—
2.	आहार एवं चारे के विकास के लिये राज्यों को सहायता	7.80	30.10	86.85
3.	राष्ट्रीय पशुधन उन्मूलन परियोजना	51.93	52.50	46.50
4.	पशु रोग नियंत्रण के लिये राज्यों को सहायता	31.17	120.08	33.60
5.	व्यावसायिक क्षमता विकास	4.00	3.35	6.42
6.	बूचड़खानों/पशुधन उपयोग केन्द्रों तथा प्राथमिक निस्स्वचन एककों के सुधार/स्थापना हेतु राज्यों को सहायता	—	81.013	179.748
7.	प्रमुख पशुधन उत्पादों के अनुमान के लिये एकीकृत नमूना संवर्धन	13.50	17.02	24.09
8.	राष्ट्रीय सड़क उत्पादन कार्यक्रम	—	33.00	25.75
9.	राष्ट्रीय मेढा/मूंग उत्पादन कार्यक्रम तथा खरबोश विकास कार्यक्रम	6.50	36.00	20.525
10.	भारतवाही पशुओं का विकास	5.25	6.70	10.40
11.	एकीकृत सुधार विकास के लिये राज्यों को सहायता	7.50	4.50	15.00
12.	पशु पालन विस्तार कार्यक्रम	—	16.50	—

दुग्ध पाउडर और बटर आयात का मूल्य

6556. प्रो. राम बख्श सिंह वर्मा :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 से आयातित दुग्ध-पाउडर और बटर आयात का बाजार मूल्य कितना-कितना है ;

(ख) उन विभिन्न एजेंसियों के बीच

आयातित दुग्ध-पाउडर और बटर आयात की कुल मात्रा का वितरण किस प्रकार किया जाता है जो वर्ष 1990 से ऐसे आयात का लाभ उठा रही हैं ; और

(ग) ऐसी एजेंसियों को लाभ दिये जाने के क्या कारण हैं ?